

डाक-बग की पूर्व-अदायगी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमति. अनुमति-पत्र
क. एम. पी. सी. 49.

पंजी क्रमांक एम.पी.--533



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 नवम्बर 1973—का.प्र. 24, शके 1895

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 1973.

क्र.प्र. 302-9-1-(जी)-23-03-इकाई-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का गिम्बलित्त
अधिनियम, जिस पर दिनांक 6 नवम्बर 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा
सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राजपत्राल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भा. रा. दुब, उपराशि.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 46 सन् 1973.

मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा
स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972

विषय-सूची

धाराएं

पहला भाग—प्रारम्भिक

1. संक्षेप नाम तथा प्रारम्भ.
2. परिभाषाएं.

धाराएं

दूसरा भाग—मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिपद्

३. उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिपद् का निर्माण.
४. परिपद् का गठन.
५. परिपद् का अध्यापक तथा उपाध्यापक.
६. निर्वाचन आदि की रीति.
७. परिपद् के उपाध्यापक तथा सदस्यों की पदावधि.
८. आर्थिक स्थिति.
९. सदस्यों की अनुपस्थिति की इजाजत.
१०. परिपद् के अधिवेशन.
११. रिजिस्टर से कार्यवाहियों आदि का प्रविधिवत् न होना.
१२. परिपद् के अध्यापक, उपाध्यापक तथा सदस्यों को भत्ते की देनगी.

तीसरा भाग—रजिस्ट्रीकरण

१३. रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारी.
१४. राज्य रजिस्ट्रार.
१५. वे व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत किये जा सकेंगे और रजिस्ट्रीकरण फीस.
१६. रजिस्ट्रीकरण के विशेषाधिकार.
१७. राज्य रजिस्ट्रार में नाम की प्रविष्टि का प्रतिषेध करने या उसमें से नाम हटाने का निर्देश देने की परिपद् की शक्ति.
१८. परिपद् द्वारा राज्य रजिस्ट्रार में परिवर्तन.
१९. जांचों की प्रक्रिया.
२०. परिपद् के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.
२१. फीस का व्यय.
२२. रजिस्ट्रीकरण के लिये प्राप्त या राज्य रजिस्ट्रार में नामांकित समस्त गये व्यक्तियों को छोड़कर व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों की सूची का रखा जाना.
२३. इन अधिनियम में उल्लिखित अवस्था को छोड़कर व्यवसाय करने का प्रतिषेध.

चौथा भाग—प्रशिक्षण संस्थाएं

२४. प्रशिक्षण संस्थाएं.
२५. संस्थाओं को मान्यता देने से इन्कार करने के विरुद्ध अपील.

पांचवां भाग—प्रकीर्ण

२६. मृत्यु की सूचना पर रजिस्ट्रार से नाम का हटाना जाना.
२७. प्रमाणपत्र को ब्रेडपानी से उपयोग में लाने के लिये शास्ति.
२८. रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका, स्वास्थ्य परिदल, को उपाधि की विधि विरुद्ध अधिधारण करने के लिये शास्ति.
२९. अपराधों का प्रसंग.
३०. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
३१. राज्य शासन द्वारा नियंत्रण.
३२. परिपद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन.
३३. नियम बनाने की शक्ति.
३४. विनियम बनाने की शक्ति.
३५. धारा ३ के अधीन परिपद् की स्थापना पर होने वाले परिणाम.
३६. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

संख्या ४६ सं १९७३

मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका
तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७२

[दिनांक ६ नवम्बर १९७३ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक १५ नवम्बर १९७३ को प्रथमवार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश में उपचारिकाओं (नर्स), प्रसाविकाओं (मिडवाइव्स), सहायी उपचारिका-प्रसाविकाओं (अनजीलिंगरी नर्स-मिडवाइव्स) तथा स्वास्थ्य परिदर्शकों (हेल्थ विजिटर्स) के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधियों का संगठन करने तथा राज्य के लिये उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् के गठन तथा उससे संबंधित विषयों के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्न-लिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :—

पहला भाग—प्रारंभिक

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ कहलायेगा। संक्षिप्त नाम निस्तार तथा प्रारंभ।

(२) इसका विस्तार-शेष संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य शासन, अधिनियम द्वारा नियत करे।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "परिषद्" से तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् से है;

(ख) "उपचारिका" में उपचारक (गेलनर्स) भी सम्मिलित है;

(ग) "पाठ्यता प्राप्त अर्हता" से तात्पर्य इंडियन नर्सिंग काउन्सिल एक्ट, १९४७ (संख्या ४८ सं १९४७) की अनुसूची में सम्मिलित किन्हीं भी अर्हताओं से है;

(घ) "राज्य रजिस्टर" से तात्पर्य धारा १४ के अधीन रखे गये रजिस्टर से है और अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकरण" तथा "रजिस्ट्रीकरण" का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा।

दूसरा भाग—मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद्

उपचारिका रजि-
स्ट्रीकरण परिषद्
का निगमन.

३. (१) राज्य शासन, यथाशक्ति शीघ्र, अधिचना द्वारा, ऐसे दिनांक से, जो कि उसमें उल्लिखित किया जाय, एक उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् की स्थापना करेगा.

(२) परिषद्, मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद् के नाम से एक निगम निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित एवं धारण करने और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने द्वारा धारण की गई किसी भी संपत्ति को अन्तर्गत करने तथा संविदा करने और उसके गठन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी या उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

परिषद् का गठन.

४. (१) परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) स्वास्थ्य सेवा संचालक, मध्यप्रदेश—पदेन;
- (ख) परिषद् द्वारा धारा २४ के अधीन अनुमोदित तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के दो अधीक्षक जो राज्य शासन द्वारा बारी-बारी नाम निर्देशित किये गये हों ;
- (ग) सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवा (उपचारिका) तथा उपाय पद के रिक्त होने की दशा में अधीक्षक, उपचारिका संचालन—पदेन;
- (घ) उपचारिका विद्यालय, इन्दौर का प्राचार्य (प्रिन्सिपल)—पदेन;
- (ङ) चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सालयों से राज्य शासन द्वारा बारी-बारी से नाम निर्देशित की गई दो प्रधान परिचारिकाएँ (मेट्रन्स) ;
- (च) मध्यप्रदेश के उपचारिका विद्यालयों की दो शिक्षक-महोपाचारिकाएँ (सिस्टर ट्यूटर्स) जो राज्य शासन द्वारा बारी-बारी से नाम निर्देशित की गई हों ;
- (छ) मध्यप्रदेश में निवास करने वाली रजिस्ट्रीकृत उपचारिकाओं में से प्रशिक्षित उपचारिका संच की मध्यप्रदेश शाखा द्वारा निर्वाचित एक उपचारिका;
- (ज) उन रजिस्ट्रीकृत उपचारिकाओं को, जो कि मध्यप्रदेश बोर्ड आफ ट्रेण्ड नर्सिंग एसोसिएशन की सदस्या हों, छोड़कर अन्य रजिस्ट्रीकृत उपचारिकाओं द्वारा अपने में से निर्वाचित तीन उपचारिका-निगम से एक उपचारक (मेल नर्स) होगा ;
- (झ) रजिस्ट्रीकृत प्रसाविकाओं द्वारा अपने में से निर्वाचित एक प्रसाविका;
- (ञ) रजिस्ट्रीकृत सहायी उपचारिका-प्रसाविकाओं द्वारा अपने में से निर्वाचित एक सहायी उपचारिका-प्रसाविका;

- (ट) रजिस्ट्रीकृत' स्वास्थ्य परिदर्शकों द्वारा अपने में से' निर्वाचित एक स्वास्थ्य परिदर्शक ;
- (ठ) रेड-क्रास संस्था की मध्यप्रदेश शाखा द्वारा मध्यप्रदेश में निवास करने वाले अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य ;
- (ड) मिड-इंडिया बोर्ड आफ एनजायनिंग द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, एक ही समय में सदस्य के रूप में एक से अधिक हैसियत में सेवा नहीं करेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में अधिगूचित किया जायगा.

५. (१) स्वास्थ्य सेवा संचालक, मध्यप्रदेश, परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा. परिषद् का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष.

(२) परिषद् का उपाध्यक्ष परिषद् के सदस्यों द्वारा उनमें से ही निर्वाचित किया जायगा.

६. (१) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ज), (झ), (ञ) तथा (ट) के अधीन निर्वाचन परिषद् द्वारा संचालित किया जायगा तथा धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (छ), (ठ) तथा (ड) के अधीन निर्वाचन उनमें निर्दिष्ट नियमों द्वारा, विहित रीति में, संचालित किया जायगा. निर्वाचन यदि की रीति.

(२) यदि धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (छ), (ठ) तथा (ड) में निर्दिष्ट निकायों में से कोई भी निकाय ऐसे दिनांक तक, जो कि विहित किया जाय, किसी व्यक्ति को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित न करे, तो राज्य शासन, लिखित आदेश द्वारा, रित्त स्थान पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो कि उस पर निर्वाचन के लिये अर्ह हो; और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति परिषद् का सदस्य समझा जायगा मानो कि वह उक्त निकाय द्वारा सम्यक् रूपेण निर्वाचित किया गया हो.

(३) जहां परिषद् के किसी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो वहां वह ऐसी कानूनावधि के भीतर, जो कि विहित की जाय, राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

७. (१) उपाध्यक्ष एक कलेण्डर वर्ष के लिये पद धारण करेगा.

परिषद् के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.

(२) पदेन सदस्य के प्रतिरित्त परिषद् का प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जिसको कि उसका निर्वाचन या नामनिर्देशन धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन राजपत्र में अधिगूचित किया गया हो, तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा:

परन्तु ऐसा सदस्य अपनी पदावधि समाप्त होने पर भी उस समय तक पद धारण किये रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन या वरण, जैसी भी की दशा हो, राजपत्र में सम्यक् रूपेण अधिगूचित न कर दिया जाय.

८. (१) कोई भी निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी भी समय अपने वाफसिंगक गितियों, हस्ताक्षरयुक्त लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता त्याग सकेगा, और तदुपरि उसका स्थान रिक्त हो जायगा.

(२) किसी भी निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य को संबंध में यह ज्ञात जायगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है, यदि—

(एक) वह परिषद् के तीन लगातार साधारण अधिवेशनों से ऐसे प्रतिहेतु के बिना अनुपस्थित रहे जो कि परिषद् की राय में पर्याप्त हो; या

(दो) वह लगातार छः मास से अधिक कालावधि के लिये भारत से बाहर रहे; या

(तीन) उसका नाम धारा १७ के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया जाय.

(३) यदि कोई ऐसा प्रश्न, विवाद या शंका उत्पन्न हो जाय कि क्या उपधारा (२) के अधीन कोई रिक्त हुई है, तो राज्य शासन द्वारा उसका विनिश्चय किया जायगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

(४) परिषद् में होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायगी और रिक्ति भरने के लिये निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अव्यतीत अवधि के लिये पद धारण करेगा.

सदस्यों को अनु-
पस्थिति की
इजाजत.

९. परिषद् किसी भी सदस्य को परिषद् के अधिवेशनों से छः मास से अधिक किसी कालावधि तक अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकेगी.

परिषद् के अधि-
वेशन.

१०. (१) परिषद् प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जो कि परिषद् द्वारा नियत किया जाय, अधिवेशन करेगी.

(२) परिषद् के पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी और परिषद् के समस्त कार्य उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे. मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत प्राप्त होगा.

रिक्ति से कार्य-
वाहियों आदि
का अविधिवत्
न होना.

११. परिषद् का कोई भी कार्य केवल इस कारण अविधिवत् नहीं होगा कि—

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में मामले के गुणगुण पर प्रभाव न डालने वाली कोई अनियमितता है.

१२. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को अधिवेशनों में हाजिर होने के लिये ऐसे भत्तों की देनगी की जायगी जिन्हें कि परिषद् विनियमों द्वारा अवधारित करे. परिषद् के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भत्ते की देनगी.

तीसरा भाग—रजिस्ट्रीकरण

१३. (१) परिषद् एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी जो परिषद् के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा. रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारी.

(२) परिषद् एक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करेगी जो परिषद् की निधियों पर व्यापक नियंत्रण रखेगा :

परन्तु कोषाध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, रजिस्ट्रार एक वर्ष से अधिक काला-वधि तक कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा, यदि परिषद् द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाय.

(३) परिषद् ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगी जिन्हें कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे.

(४) रजिस्ट्रार तथा कोषाध्यक्ष के संबंध में अर्हताएं, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें तथा वेतनमान ऐसे होंगे जो कि विहित किये जायें और अन्य कर्मचारियों के संबंध में ऐसे होंगे जिन्हें कि परिषद् राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से अवधारित करें.

(५) परिषद् रजिस्ट्रार, कोषाध्यक्ष या किसी अन्य कर्मचारी से उसके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिये ऐसी प्रतिभूति की, जैसी कि परिषद् आवश्यक समझे, अपेक्षा करेगी तथा उसे लेगी.

(६) इस धारा के अधीन परिषद् को द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार, कोषाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा २१ के तात्पर्य के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे.

१४. (१) परिषद् मध्यप्रदेश में निवास करने वाली—

राज्य रजिस्ट्रार.

(एक) उपचारिकाओं,

(दो) प्रसाविकाओं,

(तीन) सहायी उपचारिका-प्रसाविकाओं, और

(चार) स्वास्थ्य परिदर्शकों

का, जो धारा १५ के अधीन नामांकन के लिये पात्र हों, विहित रीति में एक रजिस्ट्रार एबवायेगी, जो "राज्य रजिस्ट्रार" के नाम से जाना जायगा.

(२) परिषद् के रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा कि वह राज्य रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के तथा परिषद् द्वारा दिये गये विन्हीं भी आदेशों के उपबन्ध के अनुसार रखे, और समय-समय पर रजिस्ट्रार को विहित रीति में पुनरीक्षित करे तथा उसे राजपत्र में प्रकाशित करे.

(३) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १५, १८७२) के तालाबंदी के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जायगा और राजाश्र में प्रकाशित की गई प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किया जा सकेगा।

वे व्यक्ति जो रजि- १५. मान्यता-प्राप्त ग्रहता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी ग्रहता का प्रमाण स्वीकृत किये जा रजिस्टर को देने पर तथा ऐसी फीस की, जो कि विहित की जाय, देनगी पर राज्य-सकेंगे और रजि- रजिस्टर में नामांकन के लिए पात्र होगा, और धारा १४ में वर्णित भिन्न-भिन्न व्यक्ति यों स्वीकरण फीस. के लिये भिन्न-भिन्न फीस विहित की जा सकेगी।

रजिस्ट्रीकरण के विशेषाधिकार.

१६. (१) कतिपय मान्यता प्राप्त ग्रहताएं रखने वाले व्यक्ति द्वारा उपचारिका प्रभाविका, सहायी उपचारिका-प्रभाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में व्यवसाय किये जाने के विषय में इस अधिनियम में दी गई शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम राज्य-रजिस्टर में तत्समय दर्ज हो, अपनी ग्रहताओं के अनुसार राज्य में यथास्थिति उपचारिका, प्रभाविका, सहायी उपचारिका-प्रभाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में व्यवसाय करने तथा ऐसा व्यवसाय करने के संबंध में ऐसी कोई फीस, जिसे देने का वह हकदार हो, विधि के सम्यक अनुक्रम में बरत कर देने का हकदार होगा।

(२) रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रभाविका, सहायी उपचारिका-प्रभाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति किसी भी चिकित्सालय, अस्पताल, छात्रावास, शोधालय, प्रसूतिगृह या शिक्षा-कल्याण-केन्द्र या किसी अन्य चिकित्सा या लोक स्वास्थ्य संस्था में उपचारिका, प्रभाविका, सहायी उपचारिका-प्रभाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में किसी भी नियुक्ति को धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।

राज्य रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि का प्रतिबंध करने या नाम हटाने का निर्देश देने की परिषद् की शक्ति.

१७. परिषद् रजिस्टर द्वारा निर्देश किये जाने पर या अथवा राज्य-रजिस्टर में ऐसे किसी भी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि का प्रतिबंध कर सकेगी या उसमें से उसका नाम हटाने का आदेश दे सकेगी—

(क) जो किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिये कारावास से दण्डित किया गया हो, जो परिषद् की राय में नरिंत्र संबंधी ऐसी त्रुटि को उपदर्शित करता हो जिससे कि रजिस्टर में उसका नामांकन या उसका नाम का बना रहना अवांछनीय हो जाय; या

(ख) जिसे परिषद् ने ऐसी जांच के पश्चात्, जिसमें उसी स्वयं या समुपदेशी (कौंसिल) द्वारा सुने जाने का अवसर दिया गया हो, कि जो परिषद् के विवेक से बन्द कमरे में की जा सकेगी, अधिवेशन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से किसी व्यावसायिक मामले में महित आचरण का दोषी पाया हो।

परिषद् द्वारा राज्य-रजिस्टर में परिवर्तन.

१८. (१) परिषद्, यदि वह ऐसा करने का विचार करे, तथा संबंधित व्यक्ति की सम्यक् सूचना देने तथा उसकी आपत्तियों की, यदि कोई हों, जांच करने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगी कि राज्य-रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि, जिसके संबंध में परिषद् के समुपदेशन योग्य यह सिद्ध कर दिया जाय कि वह कपटपूर्ण या अशुद्ध रूप से की गई या बनाई गई है, रद्द या संशोधित कर दी जाय।

(२) परिपद उन्हीं कारणों से, जिनसे कि धारा १७ के अधीन परिपद द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध किया जा सकेगा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका या स्वास्थ्य परिदर्शक का नाम राज्य-रजिस्ट्रार से सत्यता या किसी उल्लिखित कालावधि के अंदर हटा दिया जाय।

(३) परिपद यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२) के अधीन हटाया गया कोई भी नाम, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों और जिन्हें परिपद अधिरोपित करना उचित समझे, अधीन रहते हुए पुनः स्थापित किया जाय।

१६. धारा १५ या धारा १७ के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये, जांचों की प्रक्रिया, परिपद या धारा ३३ के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत कोई समिति भारतीय सार्वजनिक अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ सन् १८७२) के तात्पर्य के अन्तर्गत न्यायालय समझी जायगी तथा पब्लिक सर्वेण्ट्स (इन्वॉयरीज) एक्ट, १८५० (क्रमांक ३७ सन् १८५०) के अधीन नियुक्त किये गये आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी; और ऐसी जांचें, गान्ध-आय, उक्त पब्लिक सर्वेण्ट्स (इन्वॉयरीज) एक्ट, १८५० (क्रमांक ३७ सन् १८५०) की धारा ५ तथा धारा ७ से २० तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जायेंगी।

२०. (१) धारा १७ या १८ के अधीन परिपद के प्रत्येक विनिश्चय के परिपद के विनिश्चय विरुद्ध अपील राज्य शासन को प्रस्तुत होगी और उस पर राज्य शासन का विनिश्चय के विरुद्ध अपील अंतिम होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक अपील संबंधित पक्षकार को ऐसे विनिश्चय की प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से तीन मास के भीतर की जायगी।

२१. इस अधिनियम के अधीन प्राप्त समस्त जुमाने तथा इस अधिनियम के जुमाने का आयन, अधीन परिपद द्वारा प्राप्त समस्त धन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होंगे।

२२. परिपद धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन उल्लिखित किये गये रजिस्ट्रीकरण के दिनांक (जो इस धारा में इसके पश्चात् "उल्लिखित दिनांक" के नाम से निर्दिष्ट है) लिये पात्र या राज्य के ठीक पूर्व राज्य में उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका, स्वास्थ्य रजिस्ट्रार में नामांकित या दाई के रूप में व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की, जो इस अधिनियम के कित समझे गये अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं है या जो धारा ३५ के खण्ड (ग) के अधीन व्यक्तियों को छोड़ राज्य रजिस्ट्रार में नामांकित किये गये नहीं सगरे जाते हों, एक सूची बनावायेगी। कर व्यवसाय करने वाले अन्य

(२) उपधारा (१) के अधीन अने वाला तथा उसमें निर्दिष्ट की गई सूची व्यक्तियों की सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक कोई भी व्यवसायी उल्लिखित दिनांक से का रखा जाय। छः मास के भीतर रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में, विहित फीस के साथ, एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा।

परन्तु राज्य शासन अधिमूनना द्वारा, उसमें उल्लिखित किये जाने वाले कारणों से, पूर्वगत कालावधि में ऐसी और कालावधि तक की, जो तीन मास से अधिक न होगी, द्ध कर सकेगा।

(३) परिपद, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह जरूरी उचित हो, और इस बात का समाधान कर लेने के पश्चात् कि आवेदक, उल्लिखित दिनांक के ठीक पूर्ण उत्तारिका, प्रसाधिका, सहायी उत्तारिका-प्रसाधिका, स्वास्थ्य परिदर्शक या दाई के रूप में व्यवसाय कर रहा था, आवेदक का नाम उस सूची में सम्मिलित कर लेगी।

(४) धारा २० के उपबन्ध, उपधारा (३) के अधीन परिपद द्वारा पारित किये गये किसी भी आदेश को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे धारा १५ या धारा १७ के अधीन पारित आदेश को लागू होते हैं।

(५) वह व्यक्ति, जिसका नाम इस धारा के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित है, धारा १६ में उल्लिखित किये गये रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के समस्त विशेषाधिकारों का हकदार होगा।

(६) रजिस्ट्रार उपधारा (२) में उल्लिखित कानूनाधिश या ऐसी और कानूनाधिश को, जो उसके अधीन बढ़ाई जाय, समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र व्यक्तियों की उस सूची को, जो कि उपधारा (१) के अधीन तैयार की गई हो, राजपत्र में प्रकाशित करेगा और ऐसी सूचना का प्रकाशन, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार, इस बात का निश्चयायक साक्ष्य होगा कि उसमें सम्मिलित व्यक्ति यथास्थिति उत्तारिका, प्रसाधिका, सहायी उत्तारिका-प्रसाधिका, स्वास्थ्य परिदर्शक या दाई के रूप में व्यवसाय करने का पात्र है।

इस अधिनियम में उपबन्धित अवस्था को छोड़कर व्यवसाय करने का प्रतिषेध।

२३. (१) इस अधिनियम में उपबन्धित के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति राज्य में उत्तारिका, प्रसाधिका, सहायी उत्तारिका-प्रसाधिका, स्वास्थ्य परिदर्शक या दाई के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा और न स्वयं को, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस रूप में अभ्यस्तः या वैयक्तिक अभिलाष के लिये व्यवसाय करने वाले के रूप में बदलायेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (१) के उपबन्ध का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

चीया भाग—प्रशिक्षण संस्थाएं

प्रशिक्षण संस्थाएं.

२४. (१) ऐसी संस्थाएं, जो परिपद द्वारा, उसके प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किये जाने के पश्चात्, अनुमोदित तथा मान्य कर दी गई हों, उत्तारिकाओं, प्रसाधिकाओं, सहायी उत्तारिका-प्रसाधिकाओं या स्वास्थ्य परिदर्शकों को प्रशिक्षित करने लगे उन्हें परिपद के अर्हतादायक प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए भेजने के लिए सक्षम होंगे।

(२) परिपद किसी भी ऐसी संस्था की मान्यता का, अपने प्रतिनिधि द्वारा उसका निरीक्षण किये जाने के पश्चात्, प्रत्याहर्ण कर सकती है। ऐसे प्रत्याहर्ण का आदेश लिखित में होगा और लिखित रीति में उसकी तामील की जायेगी :

परन्तु संस्था के गारसाधक प्राधिकारियों की सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी भी मान्यता का प्रत्याहर्ण नहीं किया जायेगा।

(३) कोई भी विद्यालय, चिकित्सालय या अन्य संस्था, जो इस धारा के अधीन अनुमोदित तथा मान्यता प्राप्त न हो, किसी भी व्यक्ति को, जब तक कि उसका नाम इस अधिनियम के अधीन सूची में रजिस्ट्रीकृत या प्रविष्ट न किया गया हो, प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगी या किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी ऐसे दस्तावेज में प्रविष्ट नहीं करेगी जो यह प्रकट करने के लिए अभिप्रेत हो कि ऐसा व्यक्ति उसके किसी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के कारण या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने के कारण उपचारित, प्रसावित, सहायी उपचारित-प्रसावित या स्वास्थ्य परीक्षा के रूप में व्यवसाय करने के लिये अर्ह है।

(४) कोई भी व्यक्ति, जो उपाधारा (३) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोष सिद्ध पर, जुर्माने से, जो ५०० रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायगा।

(५) जब इस धारा के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कानूनी या अन्य नियम-नियम या व्यक्तियों की संस्था (चाहे नियमित हो या न हो) हो, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के लिये जाने के समय संचालक, प्रबंधक, सचिव, अभिभूत या अन्य पदाधिकारी या उसके प्रबंध से संबंधित व्यक्ति हो, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जायगा।

२५. यह अनुमोदित करने तथा मान्य करने से कि कोई संस्था उपचारितार्थों, या सहायी उपचारित-प्रसावितार्थों या स्वास्थ्य परीक्षाओं को प्रशिक्षित करने के लिये सक्षम है, परिणाम द्वारा इनकार कर दिये जाने से व्यक्ति हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसे इनकार के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसे इनकार के अधिन के विरुद्ध राज्य शासन को अपील कर सकेगा। किसी भी ऐसी अपील पर राज्य शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा।

संस्थाओं को मान्यता देने से इनकार करने के विरुद्ध अपील।

पांचवां भाग—प्रकीर्ण

२६. जन्म तथा मृत्यु का, प्रत्येक रजिस्ट्रार, जिस किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जिसके नाम के संबंध में वह जानता है कि वह किसी रजिस्टर में प्रविष्ट है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह किसी रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है तो वह ऐसी मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, जो कि उसने द्वारा हस्ताक्षरित होता और जिसमें मृत्यु के समय तथा स्थान का विवरण होगा, परिणाम की डाक द्वारा सरकार को भेजना; और तदुपरि ऐसे व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जायगा।

मृत्यु की सूचना पर रजिस्टर से नाम का हटाया जाना।

२७. कोई भी व्यक्ति जो —

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसको या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को बेईमानी से उपयोग करता है;

प्रमाणपत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिये आश्रित।

(ख) किसी निष्ठा या कष्टपूर्ण घोषणा, प्रमाणपत्र या व्यपदेशन को, चाहे वह विद्विष्ट हो या अन्यथा, करके या पेश करके अथवा कराकर या पेश कराकर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रखे गये रजिस्टर या जारी

किये गये प्रमाणपत्र से संबंधित किसी विषय में कोई भी मिथ्या

व्यपदेशन मनःपूर्वक करता है या करवाता है,

दोषसिद्धि पर, प्रथम बार के अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है और किसी पश्चात्पूर्व अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

रजिस्ट्रीकृत
उपचारिका,
प्रसाधिका, सहायी
उपचारिका-
प्रसाधिका, स्वास्थ्य
परिदशक की
उपाधि को विधि
विरुद्ध अभिधारण
करने के लिये
सारित.

२८. कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाधिका, सहायी उपचारिका-प्रसाधिका, स्वास्थ्य-परिदशक न होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाधिका, सहायी उपचारिका-प्रसाधिका या स्वास्थ्य परिदशक का नाम या उपाधि, ग्रहण करता है या उपयोग में लाता है, या किसी नाम, उपाधि, वर्णन, चिह्न या चर्च, वस्तु या साईनबोर्ड का इस आशय से उपयोग करता है जिससे यह विश्वास किया जा सके या यह जानते हुए उपयोग करता है कि यह विश्वास गिने जाने की संभावना है कि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रसाधिका, सहायी उपचारिका-प्रसाधिका या स्वास्थ्य परिदशक है, दोषसिद्धि पर, प्रत्येक अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक हो सकता है और किसी पश्चात्पूर्व अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, या साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है, या दोनों से दंडित किया जायगा।

अपराधों का
प्रसंग।

२६. (१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो कि इस संबंध में परिपक्व द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित में लिखे गये परिवाद पर ही प्रसंग करेगा अन्यथा नहीं।

(२) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का परीक्षण नहीं करेगा

संरक्षणपूर्वक
की गई कार्यवाही
का संरक्षण।

३०. राज्य शासन, परिपक्व या उसकी किसी सगति के जज या शासन अथवा परिपक्व के किसी पदाधिकारी या सेवक के निरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम के अधीन संरक्षणपूर्वक की गई हो, या जिसका संरक्षणपूर्वक किया जाना अभिप्रेत रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य वैधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

राज्य शासन द्वारा
नियंत्रण।

३१. यदि किसी भी समय राज्य शासन को यह प्रतीत हो कि परिपक्व ने इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रस्तुत किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने किया है या करना आतिरेक या दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर आतिरेक या दुरुपयोग की कार्यवाही का पाबन नहीं किया है, तो राज्य शासन, यदि वह ऐसी नुक, आतिरेक या दुरुपयोग को गंभीर प्रकार का समझे, उस नुक, आतिरेक या दुरुपयोग की विशिष्टियाँ परिपक्व को अधिशूचित कर सकेगी और यदि परिपक्व ऐसी नुक, आतिरेक या दुरुपयोग का, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियत किया जाय प्रतिकार न करे तो राज्य शासन परिपक्व का विघटन कर सकेगा और परिपक्व की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों तथा कार्यवाहियों का प्रयोग एवं पालन ऐसे व्यक्तित्व द्वारा तथा दो वर्ष से अधिक ऐसी कालाधिक के लिये जिते कि वह उचित समझे, कर सकेगा और गंभीर परिपक्व को अस्तित्व में लाने के लिये, उपाय करेगा।

परिषद् राज्य शासन को ऐसी रिपोर्ट, उसके कार्य वृत्तों की प्रतिक्रियाओं, उसके लेखों की संक्षिप्तियाँ तथा ऐसी अन्य जानकारी, जैसी कि राज्य शासन विहित करे, देगी।

३३. (१) राज्य शासन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा।

(२) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के गृह पर रखे जायेंगे।

३४. परिषद् राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से और धारा ३३ के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगी और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिभूत प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे :—

(ग) परिषद् की संगति का प्रबन्ध तथा उसके लेखाओं का रखा जाना और उनकी लेखा परीक्षा;

(घ) परिषद् के अधिवेशनों का आहूत किया जाना तथा उनका किया जाना, समय तथा स्थान जहाँ ऐसे अधिवेशन किये जाते हों, उनमें किये जाने वाले कामकाज का संचालन;

(ग) परिषद् के सदस्यों के त्यागपत्र ;

(घ) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्तव्य;

(ङ) सक्ति की निम्नलिखित का ढंग, ऐसी समितियों के अधिवेशनों का आहूत किया जाना तथा उन अधिवेशनों का किया जाना और ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन ;

परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन।

नियम बनाने की शक्ति।

अधिनियम बनाने की शक्ति।

- (न) गरिबों के रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारियों एवं सेवकों की परामर्श तथा उनकी शक्तियाँ एवं कर्तव्य तथा सेवा की श्रम अर्थात् ;
- (छ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रारों के लिये आवेदन पत्र में बतलाई जानेवाली निशितियाँ तथा उसमें दिया जाने वाला अर्हताओं का प्रमाण ;

(ज) प्रहण विभागों राज्य-रजिस्ट्रार खा जायगा ;

- (झ) कोई भी निगम जिसने लिये हुए अधिनियम के अधीन, विभागों द्वारा, उक्त विभाग जा सकेगा.

३५. धारा ३ की धारा (१) के अधीन अधिनियम में गरिबों की स्वामता के लिये उल्लिखित किये गये दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

- (क) महाकोशल नॉन रजिस्ट्रेशन क्वार्टरियल, मध्यभारत परिचरित प्रगति निगम तथा रसायन-मंदिरों परिसर तथा मध्यभारत दार्ज रजिस्ट्रार नंबर विचरित हो जायेंगे ;

धारा ३ के अधीन
परिसर में
स्थानों पर होने
वाले परिणाम.

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट काउन्सिल/परिषद्/परपद की समस्त स्थितियां तथा दायित्व धारा ३ के अधीन स्थापित परिषद् की अधिराज्य तथा दायित्व होंगे तथा समझे जायेंगे ;

(ग) ऐसी समस्त रजिस्ट्रीकृत उपचारिकाएं, प्रस्ताविकायें, सहायी उपचारिका-प्रस्ताविकाएं स्वास्थ्य परिदर्शक तथा दाइयां, जो धारा ३६ के अधीन निरस्त किसी भी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों और इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर मान्यता प्राप्त अर्हतायें रखती हों, इस अधिनियम के अधीन राज्य-रजिस्टर में यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत उपचारिका, प्रस्ताविका, सहायी उपचारिका-प्रस्ताविका या स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में नामांकित की गई समझी जायेंगी ;

(घ) पूर्वोक्त दिनांक के ठीक पूर्व, खंड (क) में निर्दिष्ट काउन्सिल/परिषद्/परपद के या उसके नियंत्रण के अधीन समस्त कर्मचारी धारा ३ के अधीन स्थापित की गई परिषद् के कर्मचारी समझे जायेंगे और जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्य उपबन्ध न किये जायें, वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे तथा उन्हीं सेवा शर्तों के अधीन होंगे जिसके कि वे ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व हकदार या अधीन थे :

परन्तु राज्य शासन की पूर्व मंजूरी के अधीन रहते हुए परिषद् इस बात के लिये सक्षम होगी कि वह जिस भी ऐसे कर्मचारी की, जो उसकी राय में परिषद् की जरूरत के लिये आवश्यक या उपयुक्त न हो, उसे ऐसी राय देने की परवाना, जो कि उसके नियोजन के निबन्धनों के अनुसार दिया जाना अपेक्षित हो, सेवा को सन्तुष्ट कर दे और ऐसा प्रत्येक कर्मचारी ऐसी छुट्टी, निवृत्ति-वेतन, भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) तथा उपदान (पेंशन्टी) का हकदार होगा जिसे कि वह सेवा के लिये अतर्पण हो जाने पर लेने या प्राप्त करने का हकदार होता माने कि उस काउन्सिल/परिषद्/परपद का, जिसके कि नियोजन में वह था, अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ हो।

परन्तु यह और भी कि यदि ऐसे कर्मचारी के नियोजन के निबन्धनों में ऐसी कोई अपेक्षा अन्तर्निहित न हो, तो वह, यदि उसने काउन्सिल/परिषद्/परपद में एक वर्ष से अधिक निरन्तर सेवा की हो, धारा ३ के अधीन स्थापित परिषद् से एक भाग के अपने वर्तमान वेतन तथा भत्तों के बराबर राशि प्रतिवर्ष के रूप में वयस्क कर्म के हकदार होगा।

(ङ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट काउन्सिल/परिषद्/परपद के समस्त अभिलेख तथा कागद धारा ३ के अधीन स्थापित परिषद् में निहित होंगे तथा उसको अन्तर्लिखित हो जायेंगे।

निरस्तः

३६. धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन परिषद् की स्थापना के लिये उल्लिखित किये गये दिनांक से, सी. पी. एण्ड वरार नरेंद्र रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९३६ (मध्यप्रदेश और वरार उपाखिला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९३६) (कपांक २३ सन् १९३६) तथा मध्यप्रदेश स्टेट्यूटरी बाडीज (रीजमल कान्ट्रोल्यूशन) एक्ट, १९५६

[मध्यप्रदेश परिणियत निकाम (प्रादेशिक गठन) अधिनियम, 1972] (क्रमांक 17 रां 1972), जहाँ तक कि वह उक्त एक्ट से संबंधित हो, मध्यभारत दाईं रजिस्ट्रीकरण विधान, 1973 (क्रमांक 22 रां 1973) तथा मध्यभारत परिचारिका, प्रसूति विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य संदर्शक रजिस्ट्रेशन विधान, 1972 (क्रमांक 2 रां 1972) निरस्त हो जायेंगे।

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 1973.

क्र. एफ. 1 (बी)-235-73-इवगिस-अ (प्रा.),--भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के खंड (3) के अनुसार में मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 46, रां 1973) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वा. रा. दुवे, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 46 of 1973

THE MADHYA PRADESH UPCHARIKA, PRASAVIKA,
SAHAI UPCHARIKA-PRASAVIKA TATHA SWASTHYA
PARIDARSHAK REGISTRARIKARAN ADHINIYAM, 1972

TABLE OF CONTENTS

Sections

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Incorporation of Nurses Registration Council.
4. Constitution of Council.
5. President and Vice-President of the Council.
6. Mode of election.
7. Term of office of Vice-President and Members of Council.

6. (1) An election under clauses (h), (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 4 shall be conducted by the Council and an election under clauses (g), (l) and (m) of sub-section (1) of section 4 shall be conducted by the bodies referred to therein in the prescribed manner.

(2) If any of the bodies referred to in clauses (g), (l) and (m) of sub-section (1) of section 4 does not, by such date as may be prescribed, elect a person to be a member of the Council, the State Government shall, by order in writing, appoint to the vacancy a person qualified for election thereto; and the person so appointed shall be deemed to be a member of the Council as if he had been duly elected by the said body.

(3) Where any dispute arises regarding any election to the Council, it shall be referred to the State Government within such period as may be prescribed and the decision of the State Government thereon shall be final.

7. (1) The Vice-President shall hold office for a term of one calendar year.

Term of office of Vice-President and Members of Council.

(2) Every member of the Council other than an ex-officio member shall hold office for a term of three years from the date, his election or nomination is notified in the Gazette under sub-section (2) of section 4:

Provided that notwithstanding the expiry of his term, such member shall continue to hold office until the election or selection, as the case may be, of his successor is duly notified in the Gazette.

8. (1) An elected or nominated member may at any time, resign his membership by tendering his resignation in writing under his hand to the President, and his seat shall thereupon become vacant.

Casual vacancies.

(2) An elected or nominated member shall be deemed to have vacated his seat if—

(i) he is absent without excuse sufficient in the opinion of the Council, from three consecutive ordinary meetings, of the Council; or

(ii) he is absent out of India for a period exceeding six consecutive months; or

(iii) his name is removed from the State Register under section 17.

(3) If any question, dispute or doubt arises whether a vacancy has occurred under sub-section (2), it shall be decided by the State Government and its decision shall be final.

(4) A casual vacancy in the Council shall be filled by election or nomination, as the case may be, and the person elected or nominated to fill the vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

MADHYA PRADESH ACT

No. 46 of 1973

THE MADHYA PRADESH UPCHARIKA, PRASAVIKA,
SAHAJ UPCHARIKA-PRASAVIKA TATHA SWASTHYA
PARIDARSHAK REGISTRİKARAN ADHINIYAM, 1972

[Received the assent of the President on the 6th November 1973, assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary) dated the 15th November 1973.]

An Act to consolidate the laws relating to registration of Nurses, Midwives, Auxiliary Nurse-Midwives and Health Visitors in Madhya Pradesh and to make provision for the constitution of the Nurses Registration Council for the State and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows:—

PART I—PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Up-Short title, charika, Prasavika, Sahaj Upcharika-Prasavika Tatha and commence-
Swasthya Paridarshak Registration Adhiniyam, 1972. ment.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definition.

(a) "Council" means the Madhya Pradesh Nurses Registration Council established under section 3;

(b) "Nurse" includes a male nurse;

(c) "recognised qualification" means any of the qualifications included in the Schedule to the Indian Nursing Council Act, 1947 (No. 48 of 1947);

(d) "State register" means a register maintained under section 14 and expressions "registered" and "registration" shall be construed accordingly.

PART II—THE MADHYA PRADESH NURSES
REGISTRATION COUNCIL

1. (1) The State Government shall, as soon as may be, Incorporation of
establish, by a notification, a Nurses Registration Council with Nurses Registra-
effect from such date as may be specified therein. tion Council.

(2) The Council shall be a body corporate by the name of the Madhya Pradesh Nurses Registration Council and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold property both movable and immovable, and subject to the provisions made under this Act, to transfer any property held by it and to contract and do all other things necessary for the purposes of its constitution and may sue or be sued in its corporate name.

Constitution
of Council.

4. (1) The Council shall consist of the following members, namely:—

- (a) The Director of Health Services, Madhya Pradesh—ex-officio;
- (b) Two Superintendents of Hospitals approved and recognised by the Council under section 24 nominated by the State Government by rotation;
- (c) The Assistant Director of Health Services (Nursing) and in the event of the said office being vacant, the Superintendent, Nursing Services—ex-officio;
- (d) The Principal, College of Nursing, Indore—ex-officio;
- (e) Two Matrons from Medical College Hospitals nominated by the State Government by rotation;
- (f) Two Sister tutors of Schools of Nursing in Madhya Pradesh nominated by the State Government by rotation;
- (g) One nurse elected by the Madhya Pradesh Branch of trained Nurses Association from amongst the registered nurses residing in Madhya Pradesh;
- (h) Three nurses elected by registered nurses other than those who are members of the Madhya Pradesh Board of Trained Nurses Association from amongst themselves of whom one shall be male nurse;
- (i) One midwife elected by registered midwives from amongst themselves;
- (j) One auxiliary nurse-midwife elected by registered auxiliary nurse-midwives from amongst themselves;
- (k) One health visitor elected by registered health visitors from amongst themselves;
- (l) One member elected by the Madhya Pradesh Branch of the Red Cross Society from amongst its members residing in Madhya Pradesh;
- (m) One member elected by Mid-India Board of Examiners from amongst its members;

Provided that no person shall at the same time serve as a member in more than one capacity.

(2) The name of every person elected or nominated under sub-section (1) shall be notified in the Gazette.

President and
Vice-President of
the Council.

5. (1) The Director of Health Services, Madhya Pradesh, shall be ex-officio President of the Council.

(2) The Vice-President of the Council shall be elected by the members of the Council from amongst themselves.

6. (1) An election under clauses (h), (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 4 shall be conducted by the Council and an election under clauses (g), (l) and (m) of sub-section (1) of section 4 shall be conducted by the bodies referred to therein in the prescribed manner.

(2) If any of the bodies referred to in clauses (g), (l) and (m) of sub-section (1) of section 4 does not, by such date as may be prescribed, elect a person to be a member of the Council, the State Government shall, by order in writing, appoint to the vacancy a person qualified for election thereto; and the person so appointed shall be deemed to be a member of the Council as if he had been duly elected by the said body.

(3) Where any dispute arises regarding any election to the Council, it shall be referred to the State Government within such period as may be prescribed and the decision of the State Government thereon shall be final.

7. (1) The Vice-President shall hold office for a term of one calendar year.

Term of office of Vice-President and Members of Council.

(2) Every member of the Council other than an ex-officio member shall hold office for a term of three years from the date, his election or nomination is notified in the Gazette under sub-section (2) of section 4 :

Provided that notwithstanding the expiry of his term, such member shall continue to hold office until the election or selection, as the case may be, of his successor is duly notified in the Gazette.

8. (1) An elected or nominated member may at any time, resign his membership by tendering his resignation in writing under his hand to the President, and his seat shall thereupon become vacant.

(2) An elected or nominated member shall be deemed to have vacated his seat if—

(i) he is absent without excuse sufficient in the opinion of the Council, from three consecutive ordinary meetings, of the Council ; or

(ii) he is absent out of India for a period exceeding six consecutive months ; or

(iii) his name is removed from the State Register under section 17.

(3) If any question, dispute or doubt arises whether a vacancy has occurred under sub-section (2), it shall be decided by the State Government and its decision shall be final.

(4) A casual vacancy in the Council shall be filled by election or nomination, as the case may be, and the person elected or nominated to fill the vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

Leave of absence to members.

9. The Council may permit any member to absent himself from the meetings of the Council for any period not exceeding six months.

Meetings of the Council.

10. (1) The Council shall meet at least once in each year at such time and place as may be appointed by the Council.

(2) Five members of the Council shall form a quorum and all acts of the Council shall be decided by the majority of the members present and voting. In the case of an equality of votes, the person presiding shall have a casting vote.

Vacancy not to invalidate proceedings, etc.

11. No act of the Council shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or defect in the constitution of the Council; or

(b) any defect in the election or nomination of a person acting as a member thereof; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Payment of allowances to President, Vice-President and members of Council.

12. There shall be paid to the President, Vice-President and members of the Council, such allowances for attending meetings as the Council may, by regulations, determine.

PART III—REGISTRATION

Registrar and other officers.

✓ 13. (1) The Council shall appoint a Registrar who shall also act as Secretary of the Council.

(2) The Council shall appoint a Treasurer who shall exercise general control over the funds of the Council:

Provided that pending the appointment of a Treasurer, the Registrar may, if so required by the Council, act as Treasurer for a period not exceeding one year.

(3) The Council may employ such other persons as it may deem necessary to carry out the purposes of the Act.

✓ (4) The qualifications, the conditions of appointment and service and scale of pay as respects the Registrar and the Treasurer shall be such as may be prescribed and as respects the other employees shall be such as the Council may, with the previous sanction of the State Government determine.

(5) The Council shall require and take from the Registrar, Treasurer or from any other employee such security for the due performance of his duties as the Council deems necessary.

[(6) The Registrar, the Treasurer and other employees appointed by the Council under this section shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

- (e) all records and papers belonging to the Council^{or} Board referred to in clause (a) shall vest in and be transferred to the Council established under **section 3**.

Repeal.

36. As from the date specified for the establishment of the Council under sub-section (1) of section 3, the Central Provinces and Berar Nurses Registration Act, 1936 (No. 23 of 1936), and the Madhya Pradesh Statutory Bodies (Regional Constitution) Act, 1956 (No. 17 of 1956), in so far as it relates to the said Act, the Madhya Bharat Dais Registration Act, 1953 (No. 22 of 1953), and the Madhya Bharat Nurses, Midwives and Health Visitors Registration Act, 1955 (No. 2 of 1955), shall stand repealed.

Health Visitors Council and the Madhya Bharat Dais, Registration Board shall stand dissolved ;

- (b) all assets and liabilities of the Councils/Board referred to in clause (a) shall belong to and be deemed to be the assets and liabilities of the Council established under section 3 ;
- (c) all such registered nurses, midwives, auxiliary nurse-midwives, health visitors and dais registered under any of the Acts, repealed under section 36 and possessing recognised qualifications on the commencement of this Act, shall be deemed to be enrolled as registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor, as the case may be, in the State Register under this Act;
- (d) all employees belonging to or under the control of the Councils/Board referred to in clause (a) immediately before the date aforesaid shall be deemed to be the employees of the Council established under section 3 and shall, until other provision is made in accordance with the provisions of this Act, receive salary and allowances and be subject to conditions of service to which they were entitled or subject immediately before such date:

Provided that it shall be competent to the Council, subject to the previous sanction of the State Government, to discontinue the service of any employee, who in its opinion, is not necessary or suitable to the requirement of the Council after giving such employee such notice as is required to be given by the terms of his employment and every such employee shall be entitled to such leave, pension, provident fund and gratuity as he would have been entitled to take or receive on being invalidated out of service as if the Council/Board in the employ of which he was had not ceased to exist:

Provided further that if the terms of employment of such employee do not contain any such requirement, he shall, if he has put in more than one year's continuous service in the Council/Board be entitled to recover from the Council established under section 3 by way of compensation a sum equal to his existing pay and allowances for one month;

Information to be furnished by Council and publication thereof.

32. The Council shall furnish such reports, copies of its minutes, abstracts of its accounts, and other information to the State Government as the State Government may prescribe.

Power to make rules.

33. (1) The State Government may, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid on the table of the Assembly.

Power to Make regulation.

34. The Council may, with the previous sanction of the State Government and subject to rules made under section 33, make regulations generally to carry out the purposes of this Act, and, without prejudice to the generality of this power, such regulations may provide for—

- (a) the management of the property of the Council and the maintenance and audit of its accounts ;
- (b) the summoning and holding of meetings of the Council, the times and places where such meetings are to be held, the conduct of business thereat ;
- (c) the resignation of members of the Council ;
- (d) the powers and duties of the President and Vice-President ;
- (e) the mode of appointment of Committees, the summoning and holding of meetings, and the conduct of business of such Committees ;
- (f) the tenure of office, and the powers and duties and other conditions of service of the Registrar and other officers and servants of the Council ;
- (g) the particulars to be stated, and the proof of qualifications to be given in application for registration under this Act ;
- (h) the form in which State register shall be maintained ;
- (i) any matter for which under this Act provision may be made by regulations.

Consequence to ensure on establishment of Council under section 3.

35. As from date specified for the establishment of the Council in the notification under sub-section (1) of section 3, the following consequences shall ensue, namely :—

3.

- (a) the Mahakoshal Nurses Registration Council, the Madhya Bharat Nurses, Midwives and

(c) wilfully makes or causes to be made any false representation in any matter relating to the register or certificate issued under the provisions of this Act;

shall, on conviction, be punished with fine which may extend to Rs. 250 for the first offence and for any subsequent offence with fine which may extend to Rs. 500 or with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with both.

28. Any person who, not being a registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor, takes or uses the name or title of registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor, or uses any name, title, description, prescribed uniform, object or sign-board with the intention that it may be believed, or with the knowledge that it is likely to be believed that such person is a registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor shall, on conviction, be punished with fine which extend to Rs. 100 for the first offence and for any subsequent offence with fine which may extend to Rs. 200 or with simple imprisonment for a term which may extend to three months or with both.

Penalty for unlawful assumption of title of registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor.

29. (1) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act, except upon complaint in writing made by the Registrar or any other officer authorised by the Council in this behalf by general or special order.

Cognizance of offence.

(2) No court inferior to that of a magistrate of first class shall try any offence punishable under this Act.

30. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Council or any committee thereof, or any officer or servant of the Government or the Council for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Protection of action taken in good faith.

31. If at any time it appears to the State Government that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it by or under this Act, or has failed to perform any of the duties conferred upon it by or under this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council, and if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within such time as the State Government may fix in this behalf, the State Government may dissolve the Council and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by such person and for such period not exceeding two years as it may think fit and shall take steps to bring into existence a new Council.

Control by State Government.

(3) No school, hospital or other institution which is not approved and recognised under this section shall issue to any person a certificate or enter the name of any person in any document purporting to show that such person is qualified by reason of his having passed any examination or undergone any course of training to practise as a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor, unless his name is registered or entered in the list under this Act.

(4) Any person who contravenes the provisions of sub-section (3) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to Rs. 500.

(5) Where a person committing an offence under this section is a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not), every person who at the time of the commission of the offence was a director, manager, secretary, agent or other officer or person concerned with the management thereof shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

Appeal against refusal to recognise institution.

25. Any person aggrieved by the refusal of the Council to approve and recognise any institution as competent to train nurses, midwives, auxiliary nurse-midwives or health visitors may appeal, within three months from the date of such refusal, to the State Government against such order of refusal. The decision of the State Government, on any such appeal, shall be final.

PART V—MISCELLANEOUS

Removal of names from register on notice of death.

26. Every Registrar of Births and Deaths who receives notice of the death of any person whose name he knows to be or has reason to believe is entered in any register, shall forthwith transmit by post to the Council a certificate or registration of such death signed by him and stating the time and place of death, and thereupon the name of such person shall be removed from the register.

Penalty for dishonest use of certificate.

27. Any person who—

- (a) dishonestly makes use of any certificate of registration issued under the provisions of this Act to him or to any other person;
- (b) procures or attempts to procure registration under the provisions of this Act by making or producing, or causing to be made or produced any false or fraudulent declaration, certificate or representation whether in writing or otherwise; or

Provided that the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein, extend the aforesaid period by a further period not exceeding three months.

(3) The Council, after making such enquiry as it deems fit to make and on being satisfied that the applicant was practising as a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife, health visitor or dai immediately before the specified date, shall incorporate the name of the applicant in the list.

(4) The provisions of section 20 shall apply to any order passed by the Council, under sub-section (3) as they apply to an order under section 15 or section 17.

(5) The person whose name is included in the list prepared under this section shall be entitled to all the privileges of a registered person specified in section 16.

(6) The Registrar shall, as soon as may be, after the expiry of the period specified in sub-section (2) or such further period as may be extended thereunder, publish the list of persons prepared under sub-section (1) in the Gazette and the publication of such list shall be the conclusive evidence of the eligibility of the person included therein to practice as a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife, health visitor or dai, as the case may be, in pursuance of the provisions of this section.

23. (1) Save as provided in this Act, no person shall practise or hold himself out, whether directly or indirectly as practising habitually or for personal gain as a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife, health visitor or dai within the State.

(2) Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be punished with fine which may extend to rupees five hundred.

PART IV—TRAINING INSTITUTIONS

24. (1) The institutions which are approved and recognised by the Council after inspection by its representative shall be competent to train nurses, midwives, auxiliary nurse-midwives or health visitors, and to send them for examination for the qualifying certificates of the Council.

(2) The Council may withdraw recognition from any such institution after its inspection by a representative of the Council. The order of such withdrawal shall be in writing and shall be served in the prescribed manner :

Provided that no recognition shall be withdrawn without giving an opportunity to the authorities in-charge of the institution from being heard.

Council be held in camera, found guilty by a majority of two-thirds of the members present and voting at the meeting of infamous conduct in any professional respect.

Alteration of
State Register
by Council.

18. (1) The Council may, if it considers it so to do, and after giving due notice to the person concerned and enquiring into his objections, if any, order that any entry in the State Register which shall be proved to the satisfaction of the Council to have been fraudulently or incorrectly made or brought about, be cancelled or amended.

(2) The Council may direct the removal altogether, or for a specified period from the State Register of the name of any registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor for the same reasons for which registration may be prohibited by the Council under section 17.

(3) The Council may direct that any name removed under sub-section (2) shall be restored subject to such conditions, if any, which the Council may deem fit to impose.

Procedure in
enquiries.

19. For the purpose of any enquiry under section 15 or section 17, the Council or any committee authorised by rules made, under section 33 shall be deemed to be a Court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), and shall exercise all the powers of a Commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), and such enquiries shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of section 5 and sections 8 to 20 of the said Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850).

Appeal against
the decision of
Council.

20. (1) An appeal shall lie to the State Government against every decision of the Council under section 15 or section 17 and the decision of the State Government thereon shall be final.

(2) Every appeal under sub-section (1) shall be preferred within three months from the date of the receipt by the party concerned of a copy of such decision.

Disposal of fine.

21. All fines realised under this Act and all moneys received by the Council under this Act shall be applied for the purposes of this Act or the rules or the regulations made thereunder.

Maintenance of
list of persons in
practices other
than those
eligible for registra-
tion or deemed
to be enrolled on
State Registers.

22. (1) The Council shall cause to be prepared a list of persons practising as nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife, health visitor or dai in the State immediately before the date specified under sub-section (1) of section 3 (hereinafter in this section referred to as the "specified date") as are not eligible for registration under the Act or are not deemed to be enrolled on the State Register under clause (c) of section 35.

(2) Any practitioner falling under sub-section (1) and desirous of getting his or her name incorporated in the list referred to therein, shall submit an application in the prescribed form together with the prescribed fee to the Registrar within six months from the specified date:

14. (1) The Council shall cause to be maintained in the State Register, prescribed manner a register of—

- (i) Nurses,
- (ii) Midwives,
- (iii) Auxiliary Nurse-Midwives, and
- (iv) Health Visitors,

resident in Madhya Pradesh who are eligible for enrolment under section 15 to be known as State Register.

(2) It shall be the duty of the Registrar of the Council to keep the State Register in accordance with the provision of this Act and of any orders made by the Council, and from time to time revise the register in the prescribed manner and publish it in the Gazette.

(3) Such register shall be deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette.

15. Every person possessing recognised qualification shall be eligible for enrolment on the State register on furnishing to the Register proof of such qualification and on payment of such fee as may be prescribed and different fee may be prescribed for different persons mentioned in section 14.

Persons who may be registered and registration fee.

16. (1) Subject to the conditions and restrictions laid down in this Act regarding practising as nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife, or health visitor by person possessing certain recognised qualifications, every person whose name is for the time being borne on the State Register shall be entitled, according to his qualifications to practice in the State as a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor, as the case may be, and to recover in due course of law in respect of such practice any fees to which he may be entitled.

Privileges of registration.

(2) No person other than a registered nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor shall be eligible to hold any appointment as nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife or health visitor in any hospital, asylum, infirmary, dispensary, maternity or child welfare centre or any other medical or public health institution.

17. The Council may, upon reference from the Registrar or otherwise prohibit the entry in, or order the removal from the State Register the name of any person—

Power of Council to prohibit the entry or to direct removal from State Register.

- (a) who has been sentenced by a Criminal Court to imprisonment for an offence indicating in the opinion of the Council such a defect in the character as would render the enrolment or continuance of his name in the register undesirable;

or

- (b) whom the Council after inquiry, at which opportunity has been given to him to be heard in person or by counsel and which may at the discretion of